साप्ताहिक

डाक पंजीयनः म.प्र./भोपाल/4-479/2019-21

RNI-MPHIN/2015/72544

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 08 मार्च 2021, वर्ष-6, अंक-49

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 8 रुपए

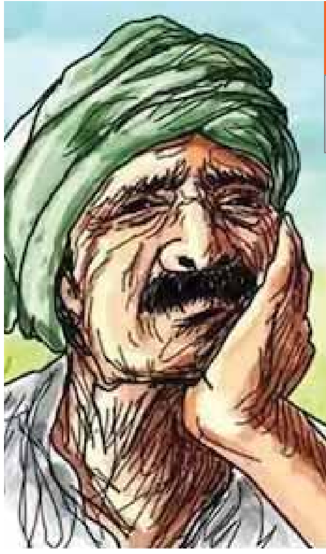

बड़ा सवाल | 2022 तक किसानों की आमदनी कैसे होगी दोगुनी

जिम्मेदारों की अनदेखी से शोभा की वस्तु बन गए 'मॉडल गांव'

कृषि विज्ञान केंद्रों के गोद लिए गांव 'अनाथ'

अरविंद मिश्र, भोपाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हर जिले के दो गांवों को गोद लिया है। इन मॉडल गांवों को डबलिंग फार्मर्स इनकम विलेज नाम दिया गया है। मप्र के 53 कृषि विज्ञान केंद्रों सहित देश के 651 केंद्रों ने गांव गोद लिए हैं। लेकिन गोद लिए गांवों में खेती-किसानी की स्थिति देखकर ऐसा नहीं लगता है कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। दरअसल, कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा गोद लिए गए अधिकांश गांवों में न तो मिट्टी परीक्षण हो पाया है, न ही किसानों को उन्नत खेती का प्रशिक्षण मिला है। जिन गांवों में मिट्टी का परीक्षण करने वैज्ञानिक पहुंचे वहां दोबारा वे लौटकर नहीं गए। आज जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते स्थिति यह है कि कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा गोद लिए गए गांवों में खेती-किसानी पुराने ढर्रे पर ही चल रही है। किसानों की आय भी नहीं बढ़ पा रही है।

किसान की आय को 2022 तक दोगुना करना है, किसान को आत्मनिर्भर और खेती को लाभ का धंधा बनाना है। अब किसानों के हर ब्लॉक में दो समूह बना रहे हैं। इसमें कम से कम 300 सदस्य और अधिक से अधिक सदस्य कितने भी बन सकते हैं। अब किसान खुद खेती करेंगे, ग्रेडिंग करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे और निर्यात भी करेंगे। जो अभी तक बिचौलिए कमाते थे, वह किसान कमाएंगे।

■ **कमल पटेल**, कृषि मंत्री

कृषि का योगदान 1/4

मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व प्रमुख दो कारणों से है। पहला कृषि क्षेत्र का योगदान मप्र की अर्थव्यवस्था में लगभग 1/4 है। दूसरा ग्रामीण जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है।

प्रदेश के मॉडल गांवों की कहानी

कृषि मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 30 राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों के 651 केवीके ने 1,416 गांवों को गोद लिया है। मप्र के 53 कृषि विज्ञान केंद्रों में से किसने कितने गांवों को गोद लिया है इसका आंकड़ा न सरकार के पास है, न विभाग के पास। '**जागत गांव हमार**' ने कृषि विज्ञान केंद्रों से संपर्क किया गया तो कुछ अधिकारियों का कहना था कि यह ऑफिशियल जानकारी है, वे यह सूचना नहीं दे सकते तो कुछ ने कहा कि इस तरह की जानकारी लेने के लिए उन्हें ई-मेल करना होगा तो कुछ अधिकारियों ने सुनते ही फोन काट दिया। कुछ जगह के फोन ही नहीं मिले।

कागजों पर मॉडल गांव

मप्र में एक तरफ किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खजाना खोल रखा है। वहीं दूसरी तरफ स्थिति यह है कि प्रदेश के 53 कृषि केंद्रों ने जिन गांवों को गोद लिया है उनमें से अधिकांश की स्थिति जस की तस है। मप्र में बैतूल, बालाघाट, छतरपुर, डिंडोरी, दमोह, हरदा, जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, पन्ना, रीवा, सागर, सिवनी, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उमरिया, रायसेन, होशंगाबाद, विदिशा, सतना, इंदौर, रतलाम, सीहोर, बुरहानपुर, आगर-मालवा, अशोकनगर, बड़वानी, भिंड, दतिया, देवास, ग्वालियर, गुना, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, मंदसौर, मुरैना, नीमच, राजगढ़, शाजापुर, श्योपुर, शिवपुरी, उज्जैन, भोपाल, अनूपपुर में 1-1 कृषि कल्याण केंद्र हैं, जबकि छिंदवाड़ा और धार में 2-2 केंद्र हैं। इनमें से कई केंद्रों ने तो गांवों को गोद तक नहीं लिया है। जिन केंद्रों ने गांवों को गोद लिया है उनमें से अधिकांश कागजों पर ही खेती-किसानी सीखा सके हैं।

मप्र में एक हजार गौ-शालाएं बनेंगी और किसानों को मिलेंगे हर साल दास हजार

विशेष संवाददाता, भोपाल

शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने दो मार्च को विधानसभा में प्रस्तुत किया। करीब 2 लाख 41 हजार करोड़ के बजट में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप के आधार पर योजनाओं के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। बजट में हर वर्ग को साधकर रखने की कोशिश की गई है। यह बजट पूरी तरह पेपरलेस था। बजट में नया कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। मप्र सरकार का कुल बजट 2 लाख 41 हजार 375 करोड़ का बजट है। इसमें व्यय का अनुमान 2 लाख 17 हजार 123 करोड़ रुपए है। कुल राजस्व घाटा 8 हजार 294 करोड़ और सकल घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटे का 4.50 प्रतिशत का अनुमान है। 2021-22 में राज्य के राजस्व में 22 प्रतिशत की वृद्धि और राजस्व व्यय में 9 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। सरकार ने सदन में बताया कि बजट के लिए जनता के 634 सुझाव मिले। इस बजट में गांव, किसान और गायों पर विशेष फोकस किया गया है। सरकार ने तय किया है कि ग्रामीण स्कूलों का 3 साल में बिजलीकरण किया जाएगा। उज्जैन की तरह जबलपुर में नए क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र को जल्द खोला जाएगा। साथ ही एक हजार ग्राम पंचायतों में 1 हजार गौ शालाएं बनेंगी और किसानों को हर साल 10 हजार रुपए मिलेंगे।

- दो लाख 41 हजार 375 करोड़ का कुल बजट
- आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश पर शिवराज का फोकस
- मप्र पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने की योजना
- होम स्टे ग्राम स्टे को विकसित किया जाएगा
- पन्ना जिला में डायमंड म्युजियम बनाया जाएगा
- छतरपुर के जटाशंकर में रोप-वे बनाया जाएगा

बजट विशेषः गांव चली सरकार देखें पेज 02 पर।

नरसिंहपुर का प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र 'बीमार'

» वन विभाग में नहीं जानकार, स्थानीय वैद्यों की तलाश

» प्राकृतिक सौंदर्य के साथ बहुमूल्य औषधियों का भंडार

संवाददाता, नरसिंहपुर

जिले के वनांचल में में प्राकृतिक सौंदर्य के साथ-साथ बहुमूल्य औषधियों का भंडार है। जरूरत है तो बस इनकी पहचान करने वालों की। एक दशक पूर्व इस दिशा में वन विभाग के एक रेंजर ने पहल करते हुए बरमान क्षेत्र में प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की स्थापना की थी, लेकिन कुछ समय तक ठीक-ठाक संचालन के बाद आज ये केंद्र कबाड़ हो चुका है। औषधियों के जानकार तक वन विभाग में नहीं बचे हैं। इसे देखते हुए जिले का वन विभाग अब प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के कायापलट की तैयारी में है। जल्द ही औषधियों के जानकारों-स्थानीय वैद्यों की तलाश कर इस केंद्र का संचालन उनके जिम्मे करेगा। 12 साल पहले वन विभाग के तत्कालीन रेंजर मथुरा प्रसाद रिछारिया ने आयुर्वेदिक औषधियों के संग्रहण और इनका प्रयोग विभिन्न बीमारियों में करने के मकसद से सतधारा के पास प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की स्थापना की थी। लेकिन रिछारिया के जाते ही केंद्र बदहाली का शिकार हो गया।

वर्तमान में भी वन विभाग में औषधियों का जानकार उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम अब स्थानीय वैद्यों-जानकारों की सेवाएं लेने की योजना बना रहे हैं। हमारा प्रयास है कि सबसे पहले बरमान समेत आसपास के वनांचल में रहने वाले औषधियों के जानकारों की तलाश की जाए। इसके लिए अधीनस्थों को निर्देशित कर दिया गया है।

महेंद्र सिंह उइके, वन मंडलाधिकारी, नरसिंहपुर

मालवा नस्ल की गायों के एक मात्र प्रजनन केंद्र के समीप खनन के लिए जमीन देने की कवायद से मंडराया खतरा

मध्य प्रदेश में भारत का एक ऐसा गौ-प्रजनन केंद्र, जहां हर गाय का नाम है और जिस गाय का नाम पुकारा जाता है, बछड़ा उसी के पास जाकर पीता है दूध

संवाददाता, भोपाल

मध्य प्रदेश के आगर मालवा में भारत का एक मात्र प्रजनन केंद्र है जहां मालवा नस्ल की गायों का प्रजनन करवाया जाता है, लेकिन अब इस प्रजनन केंद्र पर खतरा मंडरा रहा है। यह प्रजनन केंद्र अपने आप में अनूठा है, क्योंकि यहां हर गाय का नाम है और जिस गाय का नाम पुकारा जाता है, बछड़ा उसी के पास जाकर दूध पीता है। प्रजनन केंद्र, आगर मालवा की शान मोतीसागर तालाब के बिल्कुल पास बना हुआ है जहां मालवा नस्ल की देसी गायों को बचाने की कवायद कई वर्षों से चल रही है। यहां प्रजनन के लिए देसी नस्ल के बैलों को भी तैयार किया जाता है, ताकि नस्ल आगे आने वाले समय में लुप्त न हो। इस केंद्र में जितनी भी गाय हैं, सबके अपने नाम है, और सभी गाय अपने नामों को समझती हैं।

गाय का नाम लिखा : गाय को जहां बांधा जाता है वहा उसका नाम लिखा होता है। यहां कर्मचारी जिस गाय का नाम पुकारते है, उस गाय का बछड़ा आता है और अपनी मां के पास चला जाता है। बछड़े अपनी मां के नाम को समझते हैं और आवाज उन्हें लगाई जा रही है, ये भी समझते हैं। लेकिन अब इस प्रजनन केंद्र पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इस प्रजनन केंद्र के समीप थोड़ी बहुत नहीं, बल्कि 100 बीघा जमीन को 40 फीट तक खोदने की कवायद चल रही है।

प्रयासों पर फिर जाएगा पानी

नीमच की एक कम्पनी को यहां खनन के लिए मंजूरी दी जाना प्रस्तावित है। अब ऐसे में जब यहां खनन होगा तो क्या इस केंद्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां जो धूल मिट्टी उड़ेगी, यहां जो प्रजनन क्रिया होती है उस पर इस तरह के वातावरण का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां खनन शुरू हो जाता है तो वर्षों से प्रशासन द्वारा देसी नस्ल की गायों को बचाने के प्रयासों पर पानी फिर जाएगा। यह सवाल खड़े हो रहे हैं।

मप्र का बजट-2021-22: न कोई राहत, न कोई नया टैक्स

जल जीवन मिशन से गांव के हर घर में पेयजल पहुंचाया जाएगा

मध्य प्रदेश में 24200 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी

इंदौर, भोपाल और रीवा मेडिकल कॉलेज में कैंसर यूनिट बनेगी

मध्यप्रदेश में एक हजार 250 एमबीबीसी सीटें की जाएगी

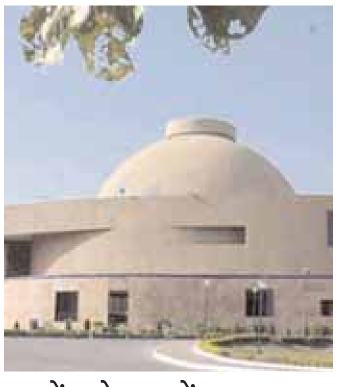

- ओंकारेश्वर में 600 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाएगी सरकार
- प्रदेश में 7 मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई
- गैस पीड़ितों को पेंशन, पुजारियों को मानदेय
- सीएम तीर्थ दर्शन योजना फिर शुरू की जाएगी
- जल जीवन मिशन के लिए 11436 करोड़ स्वीकृत
- सरकार की प्राथमिकता में कृषि में सुधार
- जीडीपी 10 ट्रिलियन पहुंचने का अनुमान
- सुपोषण वाटिका की स्थापना होगी
- एमपी को 7 बार मिल चुका कृषि कर्मण्य अवार्ड
- सहकारी बैंकों के लिए राशि बढ़ाई गई
- 65 लाख हेक्टेयर किया जाएगा सिंचाई का रकबा

गांव चली सरकार

विशेष संवाददाता, भोपाल

मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष 2021-22 का बजट दो मार्च को विधानसभा में पेश किया। नए बजट में कोरोना काल प्रदेशवासियों पर कोई नया कर नहीं थोपा गया है। डिजिटल इंडिया की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए पहली बार मध्य प्रदेश विधानसभा में पेपरलेस बजट पेश किया गया। वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि इस बार सरकार न तो कोई नया कर लगाएगी और न ही पुरानें करों में कोई बढ़ोतरी करेगी। भोपाल में पुलिस अस्पताल बनेगा और हर जिले में महिला थाना खोला जाएगा। बजट में भोपाल और इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट में 262 करोड़ दिया गया है। किसानों के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। जगदीश देवड़ा ने कहा कि किसानों को बगैर ब्याज के ऋण देने के लिए एक हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हमने किसान सम्मान निधि योजना लागू की है। किसानों को 6 हजार प्राप्त हो रहे हैं। 78 लाख किसानों को 8 हजार करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने इस योजना को टॉप अप करते हुए किसान कल्याण योजना में चार हजार रुपए और बढ़ाया है। मप्र में किसानों को 10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं।

5962
करोड़ रुपए पेयजल पर खर्च होंगे

21361
मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश में उपलब्ध

220
नए सर्व सुविधायुक्त स्कूल बनाएंगे जाएंगे

3250
मेडिकल की सीटें दी जाएंगी

घर-घर नल से जल पहुंचाएंगे

गांव और शहरों को घर-घर नल के जरिए पानी पहुंचाने के लिए बजट को साढ़े तीन गुना बढ़ा दिया गया है। अब इस पर 5962 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। पहले यह बजट 1364 करोड़ रुपए था। जल जीवन मिशन के तहत यह काम पूरा किया जाएगा। गांवों में सोलर पंप के जरिए पानी की सप्लाई कराएंगे ताकि बिजली बिलों का भार कम हो सके। स्व सहायता समूहों को 4 फीसदी पर ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन जारी रहेगी।

बिजली बिल में जनता को राहत

बजट में बिजली बिल में राहत दी गई है। 32000 करोड़ रुपए की राशि विभिन्न योजनाओं में हितग्राहियों को उपलब्ध कराई। चंबल एक्सप्रेस वे के निर्माण की कार्य शुरू कर दिया। लोक निर्माण विभाग का बजट 6866 करोड़ रुपए का है। 6064 करोड़ का पीएचई का बजट है। शहरी क्षेत्रों के लिए जलजीवन मिशन प्रस्तावित है। स्कूल और आंगनबाड़ी में पेयजल की आपूर्ति का अभियान चलाया। नवकरणीय ऊर्जा 44152 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। सीएम राइज योजना शुरू करेंगे, 9200 स्कूल सर्वसुविधायुक्त बनेंगे। मध्य प्रदेश में शिक्षण गुणवत्ता सुधार के लिए 26000 करोड़ खर्च करेंगे। अनुसूचित जाति वर्ग - ज्ञानोदय स्कूलों को सीबीएसई पाठ्यक्रम में अपग्रेड किया जाएगा। कुपोषण को लेकर पोषण नीति तैयार कर रहे हैं।

गांवों में स्कूल के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विस

9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट के लिए पांच आदिवासी बहुल जिलों में ट्रांसपोर्ट सर्विस का नया प्रयोग किया जाएगा। बैतूल के आठनेर, उमरिया के पाली, बालाघाट के बिरसा, झाबुआ और धार जिले के धरमपुरी में अगले सत्र से अंचल के स्टूडेंट को बस या अन्य यातायात सुविधा के जरिए घर से स्कूल तक लाया और ले जाया जाएगा।

किसानों को विशेष प्रावधान

किसानों के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। किसानों को बगैर ब्याज के ऋण देने के लिए 1 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हमने किसान सम्मान निधि योजना लागू की है। किसानों को 6 हजार प्राप्त हो रहे हैं। 78 लाख किसानों को 8 हजार करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने इस योजना को टॉप अप करते हुए किसान कल्याण योजना में चार हजार रुपए और बढ़ाया है। मप्र में किसानों को 10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं।

लोक सेवा गारंटी कानून में बदलाव होगा

प्रदेश सरकार ने आम लोगों से जुड़े कामों को सरल बनाने के लिए लोक सेवा गारंटी कानून में बड़ा बदलाव किया है। अब इसे डीम्ड अप्रूवल को शामिल किया है। यानी आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, नल-बिजली कनेक्शन, इलाज राशि की मंजूरी सहित 258 तरह की सरकार द्वारा आम लोगों को दी जाने वाली सेवाओं के आवेदन को अफसर लटका नहीं सकेंगे। समयावधि में या तो आवेदन मंजूर कर सेवा प्रदान करनी होगी या कारण बताकर समयावधि में ही उसे निरस्त करना होगा। यदि ऐसा अफसर नहीं करते तो पोर्टल आवेदन को स्वीकृत मान लेगा और खुद ही सेवा का ऑनलाइन सर्टिफिकेट आवेदक को जारी कर देगा।

लोक सेवा गारंटी

मिलेंगी 2441 नई सड़कें

नये बजट में प्रदेश में 2441 नई सड़कें बनाने का प्रावधान किया जाएगा। 65 नये पुल बनाए जाएंगे। इसके साथ ही 105 आरओबी बनाए जाएंगे। पीडब्ल्यूडी के लिए 7341 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

मिलेगा योजनाओं का ब्योरा

एकल्व योजना के तहत हर नागरिक का एकल डेटा बनेगा ताकि अलग-अलग सरकारी योजना या सेवाओं के लिए बार-बार दस्तावेज नहीं प्रस्तुत करना पड़ें। साथ ही हर विभाग से जुड़ी योजनाओं की जानकारी और उसे प्राप्त करने का तरीका बताने के लिए परिचय नाम से पोर्टल लांच करेगी।

वर्ष 2021-22 का प्रदेश का बजट जनता का बजट है। यह केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं अपितु प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं और जनता का प्रतीक है। यह जनता और सरकार के विजन और मिशन का प्रतिबिम्ब है। आत्म-निर्भर भारत के निर्माण के यज्ञ के मध्य लाए गए इस बजट को आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण के लिए जनता के सुझाव प्राप्त कर तैयार किया गया है। सरकार आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के लक्ष्यों को प्राप्त करेगी। इसके लिए सुशासन, भौतिक अधोसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थ-व्यवस्था और रोजगार के क्षेत्रों में मिशन एप्रोच अपनाकर गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाएगा।

शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

सावधान! डिस्पोजल कप में चाय की चुस्की छीन लेगी लोगों के आंखों की रोशनी

आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं का चौंकाने वाला खुलासा

सस्ते पेपर कप के चक्कर में खस्ती हो जाएगी लोगों की हालत

कुल्हड़ बनाने वालों को राज्य सरकारों को देनी चाहिए सब्सिडी

जनता की आवाजः मिट्टी के कुल्हड़ का उपयोग होना चाहिए अनिवार्य

अरविंद मिश्रा, भोपाल

सावधान! डिस्पोजेबल पेपर कप में गर्म पेय पदार्थ, दूध-चाय और कॉफी का पीना जानलेवा है। यही नहीं, यह लोगों को दृष्टिहीन भी कर सकता है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। गौरतलब है कि आज के समय में अधिकांश लोग कॉच की ग्लास में चाय-कॉफी पीने से परहेज करते हैं। अगर दुकानदार कॉच की ग्लास में चाय देते हैं तो लोग उसे पीने से इंकार कर देते हैं। वहीं अगर दुकानदार चाय-कॉफी डिस्पोजल पेपर कप में देता है तो लोग उसे ज्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि वो कप यूज एंड थ्रो रहता है। डिस्पोजल कप में चाय-कॉफी पीने वाले कुछ लोगों का मानना है कि कॉच की ग्लास में एक दिन में लगभग 50 लोग चाय पीते हैं। लेकिन दुकानदार उस ग्लास को सामान्य पानी से धोकर लोगों का चाय-कॉफी पिलाते हैं। जबकि डिस्पोजल कप का एक बार ही इस्तेमाल रहता है। इसलिए उसे ज्यादा उपयोगी मानते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि उसका लगातार इस्तेमाल लोगों की आखों की रोशनी तक छीन सकता है। दरअसल, आईआईटी, खड़गपुर की एक रिसर्च में पाया गया है कि इन डिस्पोजेबल पेपर कप में गर्म पेय पदार्थ पीना सही नहीं है, क्योंकि इन पेपर कप से माइक्रोप्लास्टिक सहित कई हानिकारक तत्व निकलते हैं।

शोध के दो तरीके

शोधकर्ताओं ने इस स्टडी के लिए दो तरीके आजमाए। एक- 85 से 90 सेल्सियस तापमान वाला गर्म पानी एक डिस्पोजेबल पेपर कप में डाला गया और 15 मिनट तक इंतजार किया गया। इसके बाद पानी की जांच की गई, जिसमें माइक्रोप्लास्टिक्स के कण मिले। दूसरा- 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के गर्म पानी में एक पेपर कप डुबोया। इसके बाद पेपर लेयर से सावधानी से हाइड्रोफोबिक फिल्म को अलग किया गया और गर्म पानी को 15 मिनट तक रखा गया। साथ ही, प्लास्टिक फिल्म के फिजीकल, केमिकल और मैकेनिकल बदलावों की जांच की गई।

स्वास्थ्य के लिए हानिकारक

शोध रिपोर्ट में कहा गया है कि ये माइक्रोप्लास्टिक के कण विषाक्त पदार्थों के वाहक के रूप में कार्य कर सकते हैं। इनमें पैलेडियम, क्रोमियम, कैडमियम जैसे जहरीले भारी धातु और कार्बनिक यौगिक शामिल हैं। जब इन विषाक्त पदार्थों को निगला जाता है, तो स्वास्थ्य के लिए काफी गंभीर हो सकते हैं।

मिट्टी के कुल्हड़ को मिले बढ़ावा

'जागत गांव हमार' से एक खास बातचीत के दौरान भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार पंकज शुक्ल ने कहा कि आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने जो खुलासा किया है, वह बिलकुल सही है। लेकिन डिस्पोजल पेपर कप का इस्तेमाल रोकने के लिए सरकारों का आगे आना होगा। अगर सरकार मिट्टी के कुल्हड़ का इस्तेमाल अनिवार्य कर दे तो इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार का अवसर बढ़ जाएंगे। लोग गांवों में मिट्टी के वर्तन बनाने लगेंगे। इससे हमारी संस्कृति भी बची रहेगी और एक स्वस्थ्य पीढ़ी का निर्माण भी होगा। सरकार को चाहिए कि मिट्टी के कुल्हड़ बनाने वालों को ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी दे ताकि लोग अधिक से अधिक उत्पादन करें।

इस तरह बनाते हैं पेपर कप

यह पेपर कप एक महीन हाइड्रोफोबिक फिल्म से तैयार किए जाते हैं, जो अममून प्लास्टिक (पॉलीथिलेन) से बनते हैं। कई दफा पेपर कप में तरल पदार्थ को रोकने के लिए को-पॉलीमर्स का इस्तेमाल किया जाता है। आईआईटी, खड़गपुर के सिविल इंजीनियरिंग विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर सुधा गोयल, रिसर्च स्कॉलर वेद प्रकाश रंजन और अनुजा जोसफ ने यह अध्ययन किया और पाया कि पेपर कप में 15 मिनट तक गर्म पानी रखने से माइक्रोप्लास्टिक की पतली परत क्षीण हो जाती है।

इनका कहना है

अभी हाल ही में किया गया यह अध्ययन बताता है कि ऐसे उत्पादों के इस्तेमाल से पहले सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। हमें पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को खोजना होगा, लेकिन साथ ही हमें हमारे पारंपरिक व स्थायी जीवन शैली को बढ़ावा देना होगा।

■ **प्रो. वीरेंद्र के तिवारी**, निदेशक, आईआईटी, खड़गपुर

हमारा अध्ययन बताता है कि एक पेपर कप में 85 से 90 डिग्री सेल्सियस तापमान वाला 100 मिली गर्म तरल पदार्थ अगर 15 मिनट तक रहता है तो उसमें 25 हजार माइक्रोन आकार के माइक्रोप्लास्टिक के कण निकले। इसका मतलब है कि एक औसत व्यक्ति अगर दिन में तीन बार पेपर कप में चाय या कॉफी पीता है तो वह अपने शरीर के भीतर 75 हजार सूक्ष्म माइक्रोप्लास्टिक के कण पहुंचा रहा है, जो एक व्यक्ति के आंखों को दृष्टिहीन तक कर सकता है।

■ **प्रो. सुधा गोयल**, आईआईटी, खड़गपुर

प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ये पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा है। इसलिए बायोडिग्रेडेबल चीजों को बढ़ावा देना चाहिए। इको फेंडली हों। हमार प्रयास है कि भोपाल डिवीजन के अंतर्गत जितनी भी दुकानें हैं, उन सब में प्लास्टिक पेपर कप का उपयोग न किया जाए। साथ ही मिट्टी से बने कुल्हड़ के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। रेलवे पहले से ही अधिकांश स्टेशनों में कुल्हड़ के इस्तेमाल को बढ़ाव दे रहा है।

■ **विजय प्रकाश**, सीनियर डीसीएम, रेलवे, भोपाल डिवीजन

दुकानदार घटिया क्वालिटी का प्लास्टि कप इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये ज्यादा नुकसानदेह होते हैं। इसमें गर्म चीजों का इस्तेमाल घातक होता है। इसके उपयोग से पेट, स्किन और किडनी जैसी कई गंभीर बीमारियां होती हैं। रही बात पेपर कप की तो यह पूर्णतः सेनेटाइजेन न हो पाने कारण सुरक्षित नहीं है। क्योंकि ये कई हाथों से गुजरकर हम तक पहुंचता है। सबसे उपयोगी मिट्टी के कुल्हड़ होते हैं। सिर्फ ध्यान रखना चाहिए कि जब इस्तेमाल करें तो पानी से धो लें।

■ **डॉ. रतन कुमार वैश्य**, सीनियर फिजीशियन, भोपाल

डिस्पोजल पेपर कप का उपयोग कैंसर का निमंत्रण है। इससे हमारी कृषि योग्य भूमि कुछ दिनों में बजर हो जाती है, क्योंकि ये कभी गलता नहीं है। ये धीरे-धीरे उपजाऊ जमीन की उर्वरा शक्ति को खत्म कर देता है। यही नहीं, मिट्टी पर एक परत का रूप धारण कर लेता है। इसलिए ऐसे सभी डिस्पोजल को बैन कर देना चाहिए जो स्वतः ही न समाप्त हो जाए। डिस्पोजल से गर्म पेय पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि सरकार मिट्टी के कुल्हडों का बढ़ावा दे।

■ **इंजी. कुलदीप मिश्रा**, एमटेक, सिविल, जल विद

हमारे यहां लोग चाय-कॉफी पीना डिस्पोजल और कुल्हड़ में ही पसंद करते हैं। कोरोना काल से लोगों में यह डर हो गया है कि कॉच की ग्लास अच्छे से साफ नहीं की जाती है। इसलिए लोग ग्लास से परहेज करते हैं। रही बात हमारे फायदे की तो हमें कॉच के ग्लास में ही फायदा होता है। चूंकि एक डिस्पोजल पेपर कप हमें 40 पैसे में, मिट्टी का कुल्हड़ डेढ़ रुपए में और कॉच का ग्लास दो रुपए 25 पैसे में पड़ता है।

■ **प्रशांत कोरे**, कैफे रंजीत, एमपी नगर जोन-1, भोपाल

पवन ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित करने की जरूरत

शैलेन्द्र चौहान

आज हम अपने ज्यादातर कायों को करने के लिए अधिकाधिक विद्युत उपकरण और मशीनों का उपयोग करते हैं। हमारी ऊर्जा की माँग और खपत में वृद्धि होती जा रही है जिसके कारण हमें और नए ऊर्जा स्रोतों के उपयोग की आवश्यकता होती है। अतः ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए वैकल्पिक प्रौद्योगिकी विकसित कर अनेक नए ऊर्जा के खोजे गए हैं जिन्हें गैरपारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहा जाता है।

प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन्नति के साथ ही हमारी ऊर्जा की मांग भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। आज हम अपने ज्यादातर कार्यों को करने के लिए अधिकाधिक विद्युत उपकरण और मशीनों का उपयोग करते हैं। हमारी ऊर्जा की माँग और खपत में वृद्धि होती जा रही है जिसके कारण हमें और नए ऊर्जा स्रोतों के उपयोग की आवश्यकता होती है। अतः ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए वैकल्पिक प्रौद्योगिकी विकसित कर अनेक नए ऊर्जा के खोजे गए हैं जिन्हें गैरपारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। हम अपनी उर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उन नवीनतम स्रोतों का उपयोग कर रहे है जिनका पहले उपयोग नहीं हुआ है। ऐसा ही एक प्राकृतिक और अक्षय ऊर्जा स्रोत है 'पवन' - यानि हवा अथवा वायु जिससे पवन चक्की चलती है।

पवन ऊर्जा के उपयोग की अवधारणा का विकास ई. पू. 4000 वर्ष पुराना है, जब प्राचीन मिश्र निवासी नील नदी में अपनी नावों को चलाने के लिए पाल का प्रयोग करते थे। पवन-चक्कियों तथा पन-चक्कियों ने सबसे पहले शक्ति के स्रोत के रूप में पशु शक्ति का स्थान लिया। 7 वीं शताब्दी के अरब लेखकों ने ई. 644 में फारस में मिलों का सन्दर्भ दिया है। ये मिलें साइस्ता में स्थित थीं, जो फारस (ईरान) व अफगानिस्तान की सीमा पर हैं। पवन ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। अब पवन ऊर्जा का उपयोग बढ़ रहा है। इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन, प्रचालन की लागत कम कर देता है, और अन्य जनरेटर (पारंपरिक) की तुलना में पवन ऊर्जा की लागत कम होती है। पवन ऊर्जा सुविधाएं ज्यादातर त्रि-आयामी सुविधाएं हैं जो भूमि और पारिस्थितिकी की रक्षा करती हैं।

पवन-चक्की की संरचना किसी ऐसे विशाल विद्युत पंखे के समान होती है जिसे किसी दृढ़ आधार पर कुछ ऊँचाई पर खड़ा कर दिया जाता है। पवन-चक्की की घूर्णी गति का उपयोग विद्युत जनित्र के टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है जिससे जेनरेटर द्वारा विद्युत उत्पन्न की जा सके। किसी एक पवन चक्की का निर्गत (अर्थात उत्पन्न विद्युत) बहुत कम होता है जिसका व्यापारिक उपयोग संभव नहीं होता। अतः किसी विशाल क्षेत्र में बहुत-सी पवन-चक्कियाँ लगाई जाती हैं। इस क्षेत्र को पवन ऊर्जा फार्म कहते हैं।

व्यापारिक स्तर पर विद्युत को प्राप्त करने के लिए किसी ऊर्जा फार्म की सभी पवन-चक्कियों को परस्पर जोड़ लिया जाता है, जिसके फलस्वरूप प्राप्त कुल ऊर्जा सभी पवन-चक्कियों द्वारा उत्पन्न विद्युत ऊर्जा के योग के बराबर होती है। जैसाकि हम जानते हैं कि ऊर्जा फार्म स्थापित करने के लिए एक विशाल भूमि की आवश्यकता होती है। 1 मेगा वाट के जनित्र के लिए पवन फार्म को लगभग 2 हेक्टेयर भूमि चाहिए। पवन ऊर्जा के फार्म को स्थापित करने की आरंभिक लागत अधिक होती है। इसके अतिरिक्त पवन-चक्कियों के टॉवर तथा पंखुड़ियाँ वायुमंडल में खुले होने के कारण चक्रवात, धूप, वर्षा आदि प्राकृतिक आपदाओं को सहना पड़ता हैं अतः उनके लिए उच्च स्तर के रखरखाव की आवश्यकता होती है।

डेनमार्क को पवन ऊर्जा का देश कहते हैं। जर्मनी भी इस क्षेत्र में हम से आगे है। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में पाँचवाँ स्थान है। यदि हम पवन चालित जेनरेटर द्वारा विद्युत उत्पादन की अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करें तो लगभग 45,000 मेगा वाट विद्युत शक्ति का उत्पादन कर सकते हैं। पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का एक पर्यावरण-हितैषी गित है। इसके द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए बार-बार धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती। अतः यह ऊर्जा का स्रोत काफी सस्ता होता है।

पवन ऊर्जा के उपयोग की कुछ सीमाएँ हैं - पवन ऊर्जा फार्म केवल उन्हीं क्षेत्र में स्थापित किए जा सकते हैं जहाँ वर्ष के अधिकांश दिनों में तीव्र पवन चलती हो। टरबाइन की आवश्यक गति को बनाए रखने के लिए पवन का वेग भी 15 कि मी प्रति घंटा से अधिक होना चाहिए। पवन के नहीं चलने के समय ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संचायक सेलों जैसी पूर्तिकर सुविधा का उपयोग किया जाता है। पवनशक्ति की ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है। वायु के वेग में बहुत परिवर्तन होता रहता है। कभी तो वायु की गति अत्यंत मंद होती है और कभी वायु के वेग में तीव्रता आ जाती है। अतः जिस पवन चक्की को वायु के अपेक्षाकृत कम वेग की शक्ति से कार्य के लिए बनाया जाता है वह अधिक वायु वेग की स्थिति में ठीक ढंग से कार्य नहीं करता है। इसी प्रकार तीव्र वेग के वायु को कार्य में परिणत करनेवाली पवन चक्की को वायु के मंद वेग से काम में नहीं लिया जा सकता है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने बड़े अक्षय ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने व निवेश आसान करने के लिए योजनाएं बनानी शुरू कर दी हैं, जिससे 2030 तक 450 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का नया लक्ष्य हासिल किया जा सके। इसमें घरेलू वित्तपोषण आसान किया जाना शामिल है, जिससे क्षमता विस्तार को प्रोत्साहन दिया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत वर्ष भारत का अक्षय ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य दोगुना करने की घोषणा की थी। जब परियोजनाएं शुरू होने में देरी हो रही है और राज्य इसे लाल झंडी दिखा रहे हैं। चालू वित्त वर्ष में 3 गीगावॉट लक्ष्य की तुलना में 1.1 गीगावॉट की पवन ऊर्जा परियोजनाएं शुरू हो पाई हैं।

वहीं 7.5 गीगावॉट सौर ऊर्जा के लक्ष्य की जगह 2.1 गीगावॉट क्षमता के संयंत्र चालू हो सके हैं। अब परियोजनाएं शुरू होने में देरी हो रही है लेकिन ऊर्जा की बढ़ती मांग को देखते हुए पवन ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित करने की महती आवश्यकता है।

उत्पादन को बढ़ावा देने से ही हल हो सकती है बेरोजगारी की समस्या

पुराने पड़ चुके श्रम कानूनों से उद्योग जगत को गति नहीं दी जा सकती। देश वास्तव में मैन्युफैक्चरिंग का गढ़ बने इसके लिए हर संभव जतन इसलिए भी किए जाने चाहिए क्योंकि इससे ही बेरोजगारी की समस्या का सही तरह समाधान होगा।

मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना यानी पीएलआइ का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने एक बार फिर यह कहा कि सरकार का काम उद्योग चलाना नहीं है। निःसंदेह सरकारों को उद्योग-धंधे चलाने से बचना चाहिए। यह उनका काम भी नहीं है। उनका काम तो समुचित नियम-कानून बनाना और यह देखना है कि उनका सही तरह पालन हो रहा है या नहीं? सब कुछ सरकार करे और यहां तक कि उद्योग-धंधे भी वही चलाए, आज के युग में इस समाजवादी सोच के लिए कोई स्थान नहीं रह गया है। चूंकि इधर प्रधानमंत्री बार-बार यह कह रहे हैं कि सरकार को कारोबार से हाथ खींचना होगा, इसलिए वैसे माहौल की प्रतीक्षा की जा रही है, जिसमें निजी क्षेत्र उद्योग-व्यापार करने के लिए उत्साहित हो। यह माहौल बनाने में राज्य सरकारों को केवल आगे ही नहीं आना चाहिए, बल्कि आर्थिक-व्यापारिक मामलों में नारेबाजी वाली सस्ती राजनीति करने से भी बाज आना चाहिए। प्रधानमंत्री ने घरेलू स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे सुधारों को आगे बढ़ाने की जो बात कही, वह उत्साहजनक तो है, लेकिन बात तब बनेगी, जब भारतीय उद्योगों की उत्पादकता बढ़ाने के ठोस उपाय किए जाएंगे। आज यदि चीन, दक्षिण कोरिया आदि देश मैन्युफैक्चरिंग के मामले में कहीं आगे निकल गए हैं तो अपनी बेहतर उत्पादकता के कारण।

उत्पादकता बढ़ाने की चुनौती को सरकार के साथ उद्योग जगत को भी स्वीकार करना होगा। उसे यह समझना होगा कि उत्पादकता और साथ ही गुणवत्ता के मामले में अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में खरा उतरकर ही अभीष्ट की प्राप्ति की जा सकती है। इस दिशा में ठोस प्रयास इसलिए किए जाने चाहिए, क्योंकि दुनिया में चीन के प्रति नाराजगी और अविश्वास के कारण भारत के समक्ष एक अवसर आ खड़ा हुआ है। इस अवसर को भुनाकर ही हमारे उद्योग देश के साथ दुनिया के लिए भी उत्पाद तैयार करने में सक्षम हो सकते हैं। अब जब देश को मैन्युफैक्चरिंग का गढ़ बनाने की कोशिश की जा रही है, तब श्रम कानूनों में सुधार लाने की जो गहन आवश्यकता है, उसकी भी पूर्ति प्राथमिकता के आधार पर की जानी चाहिए। भारतीय श्रम कानून अप्रासंगिक हो चुके हैं। सभी को और खासकर श्रमिकों के हितैषी होने का दावा करने वालों को यह समझना होगा कि मौजूदा श्रम कानून उद्योगों के विकास के साथ-साथ श्रमिकों के कल्याण में भी बाधक हैं। पुराने पड़ चुके श्रम कानूनों से उद्योग जगत को गति नहीं दी जा सकती। देश वास्तव में मैन्युफैक्चरिंग का गढ़ बने, इसके लिए हर संभव जतन इसलिए भी किए जाने चाहिए, क्योंकि इससे ही बेरोजगारी की समस्या का सही तरह समाधान होगा।

10 हजार एफपीओ के गठन से किसानों को मिलेगा अपनी उपज और कृषि उपकरणों का उचित बाजार: कैलाश चौधरी

केंद्र सरकार द्वारा छोटे और सीमांत किसानों के सशक्तिकरण के उद्देश्य से 'किसान उत्पादक संगठन गठन व संवर्धन' योजना की शुरुआत की गई थी। इसको लेकर सोमवार को इसके 1 वर्ष पूर्ण होने पर कृषि मंत्रालय में केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी और परषोतम रुपाला की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने 2023-24 तक देशभर में 10,000 नए कृषि उत्पादक संगठन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। सरकार किसानों की आय दुगुनी करने के अपने लक्ष्य को लेकर प्रयासरत व संकल्पित है। बैठक में कृषि मंत्रालय के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

बैठक के बाद कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार 2021-22 में 2,500 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की स्थापना करेगी। इस पर 700 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे 60 हजार किसानों को मदद मिलेगी। एफपीओ के रूप में छोटे और सीमांत किसानों के समूह के पास फसलों की बिक्री के लिए मोलभाव की ताकत मिलेगी। कैलाश चौधरी ने कहा कि 2500 एफपीओ बनाने का काम केन्द्र की उस योजना का हिस्सा है, जिसके तहत सरकार ने पांच साल में 6,865 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ 10,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा है।

चौधरी ने बताया कि एफपीओ नए कृषि कानूनों के सफल कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। किसान चाहे व्यापारियों या कंपनियों को सीधे उपज बेच रहा हो या अनुबंध खेती के जरिए खेती कर रहा है, उसे एफपीओ से बड़ी मदद मिलेगी।

केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि एफपीओ एक ऐसी व्यवस्था है जो किसानों से फल, सब्जी, फूल, मछली व बागवानी से संबंधित फसलों को खरीदकर सीधे कंपनियों को बेचा जाता है। इसमें किसान जुड़े होते हैं और उन्हें अधिक आय प्राप्त होती है। इन एफपीओ से अब तक देश के लाखों किसान जुड़कर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा एफपीओ को ग्रेडेशन करने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। कैलाश चौधरी ने कहा कि एफपीओ लघु व सीमांत किसानों का एक समूह होगा, जिससे उससे जुड़े किसानों को न सिर्फ अपनी उपज का बाजार मिलेगा बल्कि खाद, बीज, दवाइयों और कृषि उपकरण आदि खरीदना आसान होगा। सेवाएं सस्ती मिलेंगी और बिचौलियों के मकड़जाल से मुक्ति मिलेगी। अगर अकेला किसान अपनी पैदावार बेचने जाता है, तो उसका मुनाफा बिचौलियों को मिलता है। एफपीओ सिस्टम में किसान को उसके उत्पाद के भाव अच्छे मिलते हैं, क्योंकि बारगेनिंग कलेक्टिव होगी।

एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक लाख करोड़ रुपये का प्रावधान कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत वित्तीय सुविधाओं का प्रावधान किया है। इस फंड के तहत देश में कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाए जाने के लिए कदम उठाए जा रहे है। इस एक लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड का इस्तेमाल गांवों में कृषि क्षेत्र से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में किया जाएगा। इस फंड से कोल्ड स्टोर, वेयरहाउस, साइलो, ग्रेडिंग और पैकेजिंग यूनिट्स लगाने के लिए लोन दिया जाएगा। इस फंड के तहत 10 साल तक वित्तीय सुविधा मुहैया कराई जाएगी।

इस फंड से खेती से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाएगा। इस फंड को जारी करने का उद्देश्य गांवों में निजी निवेश और नौकरियों को बढ़ावा देना है। इसी तरह पीएम किसान योजना के तहत किसानों को एक साल में 6000 रुपए की राशि 3 किस्तों में दी जाती है।

किसान ने आधा एकड़ भूमि में लगाई गेहूं की 25 किस्म

बीजों के संरक्षण के लिए खरगोन के किसान ने किया नवाचार

संजय शर्मा, खरगोन

किसानों को देशी बीजों का महत्व बताने और जैविक खेती से बीजों के संरक्षण के मकसद से खरगोन के एक किसान ने नवाचार किया है। जिला मुख्यालय से करीब 17 किमी दूर बिस्टान के किसान अविनाश दांगी ने आधा एकड़ रकबे में 25 किस्म के गेहूं के बीज लगाए हैं। गेहूं के साथ अंतरवर्तीय फसल धनिया, मेथी, चना, मूली, गाजर भी लगाई है। गेहूं की बालियां आने लगी हैं। इसी बीच धनिया, मेथी, मूली, गाजर का उत्पादन शुरू हो चुका है। इस माडल को देख दूसरे किसान भी जैविक खेती में रुचि ले रहे हैं। दांगी बताते हैं वे जैविक खेती करने के साथ देशी बीजों का संरक्षण भी करते हैं। लंबे समय तक रखे रहने से बीज खराब होने की आशंका रहती है। उन्होंने बीज संरक्षित करने के साथ ही दूसरे किसानों को जैविक खेती का महत्व बताने के लिए यह प्रयोग किया है।

रिसर्च किस्म भी शामिल

आधा एकड़ में दो नवंबर को पूसा तेजस, काला गेहूं, काली बाली, करण वंदना, चावल कोटा, जौ, लोकवन, लाल गेहूं, एचडब्ल्यू 2004, एचआई 8498, लाल बाली, 009, केडी 2001, चंदोसी, बंशी, आईडी 2003, सोना मोती, हरा गेहूं, खपली, पूर्णा, सी 306, गोल दाना, यूडी 1948, डीडी 1945, एचडी 2004 किस्म के बीज खेत में लगाए। इन किस्मों में देशभर के किसानों से जुटाए गए देशी बीज के साथ ही रिसर्च किस्म भी शामिल हैं।

60 किस्मों के बीज संरक्षित

दांगी 16 वर्ष से जैविक खेती और सात वर्ष से देशी बीज संरक्षण कर रहे हैं। अब तक 60 से अधिक देशी किस्म के बीज संरक्षित किए हैं। 25 एकड़ जमीन पर पूर्णत: जैविक खेती करते हैं। जमीन मध्य प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था से पंजीकृत है। मेड़ों पर नीम, करंज आदि पेड़ लगाकर फसल की कीटों से रक्षा करते हैं। पेड़ों की पत्तियों और फलों से जैविक उत्पाद बनाते हैं। उनके पास 42 गौवंश हैं।

पुरस्कार भी मिले

दांगी को वर्ष 2018-19 में इंडिया आर्गेनिक संस्था के टॉप टेन जैविक किसानों में शामिल किया गया था। 2020 में विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर से जैविक खेती के लिए फैलोशिप दी गई। वर्ष 2020 में ही मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड से राज्य स्तरीय जैव विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया था।

50 हजार महीने की नौकरी छोड़ खेती को अपनाया

» खरगोन के संजय शर्मा को कृषि के क्षेत्र में चुना गया

» संभावनाएं जिले के चिचली के किसान ने खेती में देखी

खरगोन। मेहनत, लगन और इच्छाशक्ति से बड़े से बड़ा और असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। ऐसी ही संभावनाएं जिले के चिचली के किसान ने खेती में देखी। झारखंड में 50 हजार प्रतिमाह पाने वाले संजय शर्मा ने नौकरी छोड़ खेती की ओर रुख किया। उन्हें साहस और खेती में जैविकता को बढ़ावा देने के लिए शासन ने पुरस्कार से नवाजा गया है। शर्मा बताते हैं कि खेती में रासायनिक खादों के भरपूर उपयोग से लाभ भी हुआ, लेकिन अब फसलों में कई तरह नई-नई बीमारियां और कीटों का प्रकोप बढ़ने लगा। इन्हें कंट्रोल करने के लिए मुनाफे से अधिक खेती की लागत बढ़ने लगी। आत्मा परियोजना के अधिकारियों द्वारा जैविक खेती के बारे में दो वर्ष पूर्व बताया गया। तभी से ढाई एकड़ में जैविक के प्रयोग किए। पहले गन्ना फिर कपास व गेहूं के साथ जैविक उत्पादन किया और रासायनिक व जैविक में अंतर करने पर पाया कि जैविक खेती करने से लागत कम हो जाती है और मुनाफा की बेहतर होने लगता है। फसलों में गोबर खाद का उपयोग होने से भूमि की गुणवत्ता में भी निरंतर सुधार देखा गया। इसलिए जैविक खेती ही सर्वोत्तम खेती है। अब पूरी 36 बीघा खेती में जैविक खेती का लक्ष्य रखा है। सब मिशन आन एग्रिकल्चरल एक्सटेंशन आत्मा द्वारा प्रतिवर्ष कृषि के क्षेत्र में सर्वोतम कृषक पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2019-20 के राज्य स्तरीय सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार और सर्वोत्तम आत्मा जिला पुरस्कार 15 फरवरी को घोषित कर दिए हैं। इसमें खरगोन के संजय शर्मा को भी कृषि के क्षेत्र में चुना गया है। इस पुरस्कार में 50 हजार प्रदाय किए जाते हैं।

रेडियो पर समाचार सुनकरे किसानों को मिली जैविक खेती की प्रेरणा

झाबुआ में प्रशिक्षण लेकर बन गए उन्नात किसान, करने लगे जैविक खेती

नोमान खान, झाबुआ

समीपस्थ ग्राम सेमलकुड़िया (मोहनकोट) के किसान नगला पुत्र नाथा निनामा पहले कपास, मक्का, गेहूं, सोयाबिन इत्यादि की खेती करते थे जिससे फसलों की लागत निकाल पाना कठिन था। वे रेडियो पर नंदाजी, भेराजी समाचार सुनते रहते थे जिससे उन्हें जैविक खेती के लिए प्रेरणा मिली। जड़ी-बूटी औषधि पौधों के नाम लिखकर रखते थे और उसके अनुसार जैविक खेती करने लगे। सबसे पहले उन्होंने इंदौर में 5 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त किया। एक कंपनी में जैविक खेती के लिए प्रचार-प्रसार का कार्य किया। प्रशिक्षण प्राप्त कर जैविक खेती के संबंध में जानकारी हासिल की। 5 वर्ष किसान मित्र के रूप में जैविक खेती के क्षेत्र में कार्य किया। कृषि विभाग द्वारा उन्नात किसान के रूप में उनका चयन किया गया। उन्होंने पेटलावद तहसील में जैविक खेती के लिए किसानों को प्रेरित करने का कार्य किया।

भोपाल में लिया प्रशिक्षण

झाबुआ जिला मुख्यालय पर आयोजित प्रशिक्षण में भाग लिया जिसमें भोपाल के अधिकारी ने जैविक खेती के लिए फार्म भरवाया। उसके बाद उनके खेत तथा फसल का निरीक्षण किया गया। फिर उन्हें जैविक खेती का प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया। उन्होंने भोपाल में आयोजित 5 दिवसीय प्रशिक्षण में भाग लिया। एक बार शासन के खर्चे से प्रशिक्षण प्राप्त किया।

एक लाख की अतिरिक्त आमदनी

उद्यानिकी विभाग की सलाह पर वर्ष 2015-16 में वर्मी कम्पोस्ट यूनिट स्थापित की और अमरूद के पौधे लगाए। विभाग से अनुदान पर

इलाहाबादी सफेद, लखनऊ-49 अमरूद की जैविक खेती ड्रिप के साथ शुरू की जिससे 1 एकड़ क्षेत्र से 25 से 30 हजार रुपए की आमदनी प्राप्त होती थी। साथ ही पपीता, गोभी, मिर्च, गेंदा, हल्दी की अंतरवर्तीय फसल ली जिस पर 20 से 25 हजार की लागत आ जाती है और उससे एक लाख की अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर लेते हैं।

साल में ले रहे तीन फसल

खेती में घर के ही सदस्य कार्य करते हैं। वे वर्षभर में तीन फसलें लेते हैं और 70 हजार रुपए खेती की लागत आती है और उन्हें 2 लाख रुपए की शुद्ध आय प्राप्त हो जाती है। अब उनके परिवार की आर्थिक स्थिति एवं जीवन स्तर में बदलाव आया है और परिवार के लालन-पालन अच्छी तरह से करने के साथ ही बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान दे पा रहे हैं।

पेटलावद में हो रहा स्ट्राबेरी का उत्पादन

इधर, पेटलावद क्षेत्र का टमाटर और शिमला मिर्च अन्य देशों तक में निर्यात होता है। क्षेत्र का किसान उन्नातशील व व्यावसायिक खेती की ओर बढ़ रहा है। क्षेत्र के किसानों द्वारा कश्मीर क्षेत्र में उत्पादित होने वाली स्ट्राबेरी का भी उत्पादन किया जाने लगा है। क्षेत्र के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। किसानों द्वारा मक्का, कपास की फसल बोई जाती थी, किंतु 25 वर्षों में किसानों द्वारा तरक्की करते हुए गेहूं, चना, तिलहन, दाल, सब्जियों की खेती की जाने लगी है। ग्राम बावड़ी के किसान जितेंद्र पाटीदार ने बताया कि जब उनके खेत पर स्ट्राबेरी की फसल आ जाती है तो वे पेटलावद सहित अन्य जगहों से पहले से आए आर्डरों पर डिलीवरी दे देते हैं। इससे हाथोहाथ स्ट्राबेरी बिक जाती है। अभी स्ट्राबेरी का थोक भाव 150 रुपए प्रति ट्रे (1 किलो 200 ग्राम) बिक रही है। ग्राहक तो खेत में ही आकर ले जाते हैं।

अनुकूल जलवायु: कृषि विशेषज्ञों के अनुसार स्ट्राबेरी की फसल के लिए जलवायु का शीतल व ठंडा होना आवश्यक है और इसीलिए विशेष रूप से इसका उत्पादन कश्मीर जैसे ठंडे क्षेत्र में होता है, किंतु झाबुआ जिले में पेटलावद के आसपास बावड़ी, बनी, सारंगी व तीतरी क्षेत्र में किसानों द्वारा विशेष व्यवस्था तथा तकनीकों के साथ स्ट्राबेरी फल का उत्पादन किया जा रहा है जिसका सीधा अर्थ यह है कि इस फल के उत्पादन के लिए क्षेत्र की जलवायु उपयोगी साबित हो रही है।

सरकार से दरकार: विदेशों में निर्यात होने वाले स्ट्राबेरी फल जो कि औषधि का भी काम करता है, का उत्पादन करने वाले इस क्षेत्र के किसानों को यदि शासन की ओर से आर्थिक सहायता तथा उन्नात तकनीक व संसाधन मुहैया कराए जाएं तो निश्चित तौर पर स्ट्राबेरी की खेती लाभ का धंध बन सकता है और प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री का खेती को लाभ का धंधा बनाने का सपना साकार हो सकता है।

नर्मदापुरम संभाग में 3.31 लाख हेक्टेयर में होगी मूंग की बोवनी

तवा बांध में पर्याप्त पानी होने से रकबा बढ़ाने का बनाया प्लान

संवाददाता, होशंगाबाद

नर्मदापुरम संभाग में इस बार तीसरी फसल मूंग की बोवनी 3 लाख 31 हजार हेक्टेयर में की जाएगी। अभी हाल ही में कृषि विभाग ने लक्ष्य तय किया है। इस बार बारिश अच्छी होने से तवा बांध में पर्याप्त पानी होने से मूंग की फसल का रकबा तीन वर्ष बाद बढ़ाए जाने का प्लान बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में खाद्यान के साथ-साथ अब फलों के उत्पादन की ओर भी किसानों की रुचि बढ़ती जा रही है। पहले नर्मदा और तवा के तरबूज, खरबूज बड़ी मात्रा में आते थे, लेकिन अब डंगरबाड़ियों में फलों की जगह सब्जियों की फसलें ज्यादा हो रही हैं। अब रेत की बजाए खेतों में तरबूज की फसलें हो रही हैं। इससे तरबूज का उत्पादन तेजी से बढ़ गया है। गर्मी बढ़ने के साथ ही बाजार में इसकी मांग भी खासी बढ़ जाती है। अभी बाहर से तरबूज की खेप आ रही है। एक माह बाद स्थानीय तरबूज की फसल आना शुरू हो जाएगी।

दो लाख हेक्टेयर का लक्ष्य: होशंगाबाद जिल में इस बार 2 लाख हेक्टेयर में मूंग की फसल लगाई जाएगी। बीते वर्ष 1 लाख 82 हजार हेक्टेयर में मूंग लगाई गई थी। जून के प्रथम सप्ताह में बारिश शुरू हो जाने से मूंग की पूरी कटाई नहीं हो पाई थी। इस कारण इस बार जल्द ही बोवनी होगी।

हरदा में होगी बोवनी: कृषि मंत्री कमल पटेल के गृह जिला हरदा में चना की कटाई शुरू हो गई है। अगले सप्ताह से खेत खाली होने के साथ ही मूंग की बोवनी की तैयारी

शुरू हो जाएगी। बीते वर्ष हरदा में 82 हजार 500 हेक्टेयर में मूंग की बोवनी हुई थी। वहीं उड़द की बोवनी 30 में हुई थी।

बैतूल में कम होती है मूंग: संभाग में सबसे कम बोवनी बैतूल जिले में होती है। बीते वर्ष 3 हजार हेक्टेयर में ही मूंग लगाई गई थी। इस बार 6 हजार हेक्टेयर में मूंग और 100-100 हेक्टेयर में उड़द व मूमफली लगाने का लक्ष्य तैयार किया जा रहा है।

कम समय की फसल

गर्मी के मौसम की मूंग को सिर्फ 60 दिन ही लगते हैं। इससे भी कम समय में तरबूज की फसल होने लगती है। इस कारण किसानों का रुझान मूंग और तरबूज की फसल लगाने में लग रहा है। जैसे ही चना और गेहूं की कटाई होगी उसके तुरंत बाद मूंग और तरबूज की फसल लगाई जाएगी।

हरदा व सिवनी मालवा तरफ चना की फसल पक चुकी है। कहीं-कहीं तो कटाई शुरू होने लगी है। एक पखवाड़े में अधिकांश क्षेत्र की चना की फसल कट जाएगी। कुछ हिस्सों में गेहूं की भी कटाई शुरू हो जाएगी। मार्च के आखिरी सप्ताह से मूंग की बोवनी शुरू हो जाएगी।

■ जितेंद्र सिंह, संयुक्त संचालक, नर्मदापुरम संभाग

लोगों की होती है लकवा बीमारी, जड़ से नष्ट करना ही विकल्प

तेवड़ा खरपतवार मानव शरीर के लिए घातक : वैज्ञानिक

संवाददाता, छतरपुर

तेवड़ा खरपतवार मानव शरीर के लिए घातक है। इसमें पाया जाने वाले न्यूरोटॉक्सिन का शरीर में संचयन होने पर मनुष्य में लकवा जैसी घातक बीमारी होती है। इसीलिए तेवड़ा खरपतवार को जड़ से नष्ट करने के लिए जरूरी है कि खेत में ही इसका उन्मूलन किया जाए। जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय नौगांव द्वारा छतरपुर जिले के कृषकों से अपील की गई है कि चने की फसल में उपजे तेवड़ा खरपतवार जिसे घास मटर के नाम से भी जाना जाता है, को नष्ट करना मानवीय जीवन के लिए अनिवार्य है। कृषक जिनकी चने की फसल 60 से 70 दिन की अवस्था पर है उनके लिए इस समय तेवड़ा खरपतवार को उखाड़कर फेंकने का सबसे उचित समय है। इस अवस्था में खरपतवार में पुष्पन एवं फलन की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही होती है। इसीलिए इसे जड़ से समाप्त करने के लिए यह अवस्था उपयुक्त है। खरपतवार को समाप्त करने से कृषक के चने की फसल साफ एवं स्वच्छ होती है और तेवड़ा खरपतवार रहित उपार्जन को बेचने पर कृषकों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। चने की खड़ी फसल में तेवड़ा खरपतवार के प्रकोप की स्थिति है तो हाथों द्वारा प्रथम निंदाई 40 से 45 दिन की अवस्था पर और द्वितीय निंदाई 60 से 65 दिन क अवस्था पर जरूर करें। ऐसे कृषक जिनकी चना फसल में तेवड़ा का पौधा प्रतिवर्ष दृष्टिगत होता है वह फसल चक्र पद्धति अपनाएं और खरपतवार के उपयुक्त प्रबंधन के लिए रासायनिक नींदानाशक दवा फ्लूक्लोरालीन (बैसालीन) 50 प्रतिशत, ईसी का 0.75 किलोग्राम सक्रिय तत्वों प्रति हेक्टेयर की दर से बुवाई के समय पर प्रयोग करें। ऐसा करने से तेवड़ा खरपतवार पर 80 प्रतिशत तक नियंत्रण पाया जा सकता है। इस प्रयोग से आगामी चने की फसल में खरपतवार आने की संभावना न्यूनतम रहती है।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जनपद पंचायतों के सीईओ और विकासखंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों को संबोधित पत्र में अवगत कराया गया है कि 15 मार्च से चने के साथ-साथ मसूर, सरसों का उपार्जन शुरू होगा। उपार्जन केन्द्रों से समर्थन मूल्य पर तेवड़ा रहित चना किया जाएगा। इसके लिए किसानों को खेतों से तेवड़ा खरपतवार के पौधे को नष्ट करने के लिए जागरूक बनाएं। -शीलेंद्र सिंह, कलेक्टर, छतरपुर

अब गैर इमारती लकड़ी के उत्पादों का प्रबंधन सीखेंगे युवा

संवाददाता, रेहटी

गैर इमारती लकड़ी के वन उत्पादों पर आधारित जीविकोपार्जन के लिए सहभागियों को बुनियादी कौशल ज्ञान प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। इसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूएफ एनविस आरपी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सहयोग कि या जा रहा है। इसके तहत हरित कौशल विकास कार्यक्रम जीएसडीपी के अंतर्गत गैर-इमारती लकड़ी के वन उत्पादों, एनटीएफपी उत्पादों, औषधीय पादपों का मूल्य संवर्धन और विपणन के संबंध में जीएसडीपी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम की शुरुआत की जा रही है।

इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य गैर इमारती लकड़ी के वन उत्पादों पर आधारित जीविकोपार्जन के लिए सहभागियों को बुनियादी कौशल ज्ञान प्रदान करना है। पाठ्यक्रम में एनटीएफपी की जीवनावधि में वृद्धि करने, क्षमता निर्माण और उनको बाजार संपर्कता प्रदान करने के लिए एनटीएफपी के मूल्य संवर्धन में अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण शामिल है। पाठ्यक्रम के लिए पिछले दिनों एक टीम ने भोपाल सहित सीहोर जिले का दौरा किया।

इसी कड़ी में टीम रेहटी स्थित औषधि प्रसंस्करण केंद्र में भी पहुंची और यहां तैयार हो रहे उत्पादों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान प्रबंधक सुरेश यादव ने इकाई के कार्यकलापों के बारे में विस्तृत जानकरी प्रदान की। वहीं समिति के वेद पंडित प्रेम नारायण शर्मा ने भी प्रकाश डाला। इस दौरान प्रोफे सर प्रद्युत भट्टाचार्य तथा जीजीएसआईपीयू के विशेषज्ञ डॉ. प्रिया भल्ला, डॉ. आएशा खोसला, राजीव कुमार, संदीप कुमार, अभिजिता सीएस सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

मध्य प्रदेश में धान के साथ उगा रहे मौसमी सब्जियां, कमा रहे लाखों

गोपालदास बंसल, शहडोल

शहडोल जिले की जनपद पंचायत सोहागपुर के भ्रमण के दौरान कलेक्टर सतेन्द्र सिंह ने ग्राम चंदनिया खुर्द के किसान संतोष पटेल के फार्म हाउस पहुंचकर उनके द्वारा लगाए गए कृषि फसलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पटेल ने बताया कि लगभग 21 एकड़ में उनके द्वारा धान एवं सब्जी का उत्पादन किया जाता है। वर्तमान में टमाटर, धनिया पत्ती, गोभी फूल, हरी मिर्ची, मटर तथा अरहर की उन्नतशील एवं आमदनी को दुगुना करने वाली सब्जी एवं दलहनी फसलों का उत्पादन किया जाता है। किसान संतोष पटेल ने कलेक्टर को बताया कि 5 एकड़ में टमाटर, 3 एकड़ में हरी मिर्च, 3 एकड़ में फूलगोभी, 3 एकड़ में अरहर, 1 एकड़ में मटर आदि लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि यदि पैदावार अच्छी होती है तो वर्ष भर में 15 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक की आमदनी हो जाती है। उन्नतशील कृषक ने बताया कि उन्हें कृषि विभाग से सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है। कृषि यंत्र जैसे-ट्रेक्टर, स्प्रिंगर इत्यादि की सुविधाएं भी कृषि विभाग की जनहितकारी योजनाओं द्वारा प्राप्त हुई है।

छत्तीसगढ़ तक जाता है चावल: संतोष पटेल के खेत का चावल और सब्जी छत्तीसगढ़ राज्य तक जाती है। इसके अलावा पड़ोसी जिला उमरिया के चिरमिरी नौरोजाबाद क्षेत्रों में विक्रय हेतु जाती है। उन्होंने बताया कि स्प्रिंगर एवं ड्रिप पद्धति द्वारा खेती की सिंचाई की जाती है। टपक प्रणाली द्वारा माइक्रो पोषक तत्व के साथ-साथ अन्य आवश्यक तत्व पौधों को बराबर मात्रा में मिल जाते हैं जिससे खेती अच्छी होती है।

कलेक्टर बोले शिमला मिर्च भी पैदा करें: किसान संतोष पटेल के पिता मुन्ना पटेल से भेंट की और उनसे कृषि करने के तरीकों से रूबरू हुए। कलेक्टर ने उनके द्वारा तैयार की गई सब्जियों की सराहना करते हुए कहा कि हल्दी, मशरूम, शिमला मिर्च, तरबूज की पैदावार भी करें इससे उनके आमदनी में और अधिक वृद्धि होगी। कलेक्टर ने उप संचालक कृषि को निर्देशित किया कि ऐसे उन्नतशील किसानों को शासन की किसान पोषित हर योजना का लाभ दिया जाए।

हल्दी प्रोसेसिंग यूनिट पर फोकस: संभागीय संयुक्त संचालक कृषि के साथ फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी के द्वारा एक जिला-एक उत्पाद हल्दी, मुनगा पत्ती, मशरूम एवं शहद के अंतर्गत किसानो के हितार्थ किए जा रहे कार्यों का अवलोकन किया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी प्रदीप सिंह ने बताया कि जिले के 580 किसानों को जोड़ा गया है। जो हल्दी, मुनगा पत्ती, मशरूम एवं शहद आदि की पैदावार कर रहे हैं। इन किसानो से खरीदकर उन्हें उचित कीमत दी जाती है, जिससे किसानों के आय में वृद्धि होती है। भ्रमण के दौरान कलेक्टर ने आत्मा परियोजना शहडोल द्वारा स्थापित हल्दी प्रोसेसिंग यूनिट का अवलोकन किया। कलेक्टर को बताया कि लगभग 50 क्विंटल हल्दी की प्रोसेसिंग इस यूनिट के द्वारा की जा रही है और सतत प्रयास किया जा रहा है कि हल्दी प्रोसेसिंग की मात्रा बढ़ाई जाए।

-किसान परपंरागत खेती को छोड़ उद्यानिकी की ओर अग्रसर

हैदराबाद में पढ़ा पाठ अब बदनावर में करेंगे ड्रैगन फ्रूट की खेती

अमरूद, नींबू, अनार, स्ट्राबेरी की खेती बड़े स्तर पर की जा रही

राजेश वैद्य, बदनावर

तहसील में पश्चिमी क्षेत्र के प्रगतिशील किसान परपंरागत खेती को छोड़ उद्यानिकी की ओर अग्रसर हो गए हैं। यही कारण है कि यहां अमरूद, नींबू, अनार, स्ट्राबेरी की उद्यानिकी बड़े स्तर पर की जा रही है। यहां के फलों की मांग देश की राजधानी दिल्ली, आर्थिक राजधानी मुंबई, गुजरात, राजस्थान समेत देश अन्य प्रांतों में भी हैं और वहां के व्यापारी यहां खरीदी करने भी आते हैं। अब किसान विदेशों से आयातित ड्रैगन फ्रूट (कमलम) की खेती की ओर रुझान कर रहे हैं। इसके लिए ग्राम जाबड़ा के 6 किसान गोपाल पाटीदार, राजू पाटीदार, दिनेश पटेल सुनील शर्मा, राधेश्याम पाटीदार, गगन पाटीदार पिछले दिनों तेलागांना में हैदारबाद के निकट कोंडापुर सांगारेडडी में ड्रैगन फ्रूट की खेती देखने के लिए गए थे। वहां उन्होंने खेती करने के तौर तरीके, बाजार की मांग, खपत आदि के बारे में जानकारी ली। ड्रैगन फ्रूट की फसलों का अवलोकन कर खेती करने के गुर सीखकर आए हैं। शीघ्र ही इसकी खेती करने की योजना को मूर्त रूप देंगे। ग्राम जाबड़ा, तिलगारा, संदला, रूपाखेड़ा, करणपुरा, संदला, भैंसोला आदि के किसानों ने टमाटर, मिर्च एवं सोयाबीन की फसलों में होने वाली नुकसानी के कारण उद्यानिकी की ओर रुझान कर लिया है।

धीरे-धीरे बढ़ रहा रकबा

किसानों को शासन की ओर से अनुदान भी दिया जाता है। इसलिए वर्तमान में यहां 300 हेक्टेयर में अमरूद, 250 हेक्टेयर में नींबू, 10 हेक्टेयर में स्ट्राबेरी के अलावा एप्पल बेर, अनार, स्ट्राबेरी, पपीता, डिवाइन गुलाब आदि की सफलतापूर्वक उद्यानिकी कर रहे हैं। यहां के फलों की मांग अन्य प्रदेशों में होने और मुनाफा मिलने से धीरे-धीरे इनका रकबा वर्ष दर वर्ष बढ़ रहा है। अब किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती करने का मन बना रहे हैं।

एक एकड़ में छह लाख खर्च

किसानों का कहना है कि ड्रैगन फ्रूट की खेती करना महंगा सौदा जरूर है। एक एकड़ में करीब छह लाख रुपए का खर्च आता है। इनमें पौधे, ड्रिप, सीमेंट के पोल आदि शामिल हैं। एक एकड़ में 1200 पौधे लगेंगे। एक खंभे के आसपास चार पौधे लगाए जाएंगे, जो उसके सहारे बड़े होंगे। इसी पर फल लगेंगे। फिलहाल छह माह में पौधे उपलब्ध हो पाएंगे। यहां की भूमि रेतीली है, जो इस फसल के लिए उपयोगी है।

यह है ड्रैगन फ्रूट

ड्रैगन फ्रूट दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। अब इसे पटाया, क्वीसलैंड, पश्चिमी आस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स भी उगाया जाने लगा है। अभी यह निर्यात किया जाता है, किंतु भारत में भी इसकी खेती होने लगी है और यहां इसका नाम कमलम कर दिया गया है। यह बेल पर लगने वाला फल है, जो कैक्टेसिया फैमिली से संबंधित है। यह सफेद गूदे वाला और लाल गूदे वाला दो प्रकार का होता है। इसके फूल भी बहुत सुंगधित होते हैं, जो रात में खिलते हैं। इसका उपयोग सलाद, मुरब्बा, जैली और शेक बनाकर किया जा सकता है।

विटामिन का भंडार

ड्रैगन फ्रूट में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। इसमें प्राकृतिक एंटीआक्सीडेंट प्रभाव के साथ-साथ फ्लेवोनोइड, फैनोलिक एसिड, एस्कार्बिक एसिड फायबर होता है। ये सभी तत्व ब्लड शुगर की मात्रा को नियंत्रित करने तथा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। यह लोगों स्वस्थ रखने के साथ कुछ शारीरिक समस्याओं से उभरने में मदद कर सकता है।

छिंदवाड़ा : 115 केंद्रों पर होगी गेहूं खरीदी

2.60 लाख क्विंटल खरीदी का रखा लक्ष्य

संवाददाता, छिंदवाड़ा

जिले के 98 पंजीयन केंद्रों में 64 हजार किसानों के गेहूं बेचने का पंजीयन कराया है। 25 फरवरी तक पंजीयन की तिथि थी, जिसके बाद जिन किसानों के आवदेन केंद्रों पर पहुंच गए थे उन्हें भी पंजीयन में शामिल किया गया है, जिसके बाद आकंड़ा बढ़ गया है। किसान शासन द्वारा निर्धारित किए गए 115 खरीदी केंद्रों में अपना गेहूं लेकर पहुंचेंगे। विभाग ने भी इस वर्ष का अपनी खरीदी का आंकड़ा बढ़ाया है, जहां पिछले वर्ष दो लाख 33 हजार क्विंटल गेहूं की खरीदी की गई थी। इस बार दो लाख 60 हजार क्विंटल खरीदी का लक्ष्य रखा है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष गेहूं का रकबा बढ़ा है, जिससे पैदावार भी अच्छी होने की उम्मीद जताई जा रही है। आने वाले दिनों में शासन खरीदी केंद्र भी निर्धारित करेगी जिसके बाद एक अप्रैल से गेहूं की खरीदी की जाएगी। पिछले वर्ष दो लाख 35 हजार हेक्टेयर में गेहूं का रकबा था, जबकि इस वर्ष गेहूं का रकबा दो लाख 75 हजार हेक्टेयर है। वहीं पंजीयन की बात की जाए तो पिछले वर्ष पंजीयन का आंकड़ा 38 हजार था, जो इस बार बढ़कर 64 हजार पहुंच गया है।

बढ़ाए गए खरीदी केंद्र

पिछले वर्ष जिले में 105 गेहूं खरीदी केंद्र बनाए गए थे, लेकिन पंजीयन की संख्या देखते हुए जिले में इस बार खरीदी केंद्र 115 बनाए गए है। 15 मार्च से पहले इन सभी खरीदी केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं बना ली जाएगी। किसानों को भी उनके खरीदी केंद्रों की जानकारी दे दी जाएगी। जिन स्थानों पर खरीदी केंद्र बढ़ाए गए हैं। वहां पर पूर्व से यह मांग उठ रही थी कि किसानों की सुविधा के हिसाब से खरीदी केंद्र बढ़ाए जाए।

इनका कहना है

जिले में किसानों की पंजीयन संख्या 64 हजार पहुंच गई है। जिन किसानों के आवेदन जमा हो गए थे उन्हें पंजीयन में शामिल किया गया है। इस बार 115 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर एक अप्रैल से खरीदी शुरू की जाएगी। गेहूं खरीदी का लक्ष्य भी 2 लाख 60 हजार क्विंटल रखा गया है।

जीपी लोधी, जिला आपूर्ति अधिकारी, छिंदवाड़ा

अगरकरा की फसल में बीज से लेकर जड़ तक मुनाफा

संवाददाता, बिल्किसगंज

कोरोना को लेकर जहां एक तरफ लोग डरे हुए हैं और रोजगार की कमी से परेशान हैं। वहीं कुछ लोगों ने सूझ-बूझ से अपनी आमदनी बढ़ा ली है। कोरोना में औषधी की मांग बढ़ने से उनके दामों में उछाल आया है। साथ ही जिन फसलों से औषधी बनती है। उनके भावों में भी उछाल आया है। इसी को देखते हुए जिले के किसान धर्मेंद्र चतुर्वेदी ने औषधीय पौधों की फसल शुरू कर दी है। बिल्किसगंज के किसान धर्मेंद्र ने अपनी पांच एकड़ भूमि पर अश्वगंधा की बोवनी की है। वहीं साढ़े तीन एकड़ पर अगरकरा की बोवनी की है। इस औषधीय पौधे की जड़ सबसे महंगी बिकती है। हांलाकि इसकी जड़ से लेकर भूसा भी दो हजार रुपए क्विंटल बिकता है और बीज एक हजार रुपए किलो तक बिकता है। औषधीय पौधों की फसल में तीन गुना तक कमाई है। धर्मेंद्र बताते हैं कि इन दिनों खेती में बढ़ती लागत व कम आय को देखते हुए क्षेत्र के कई किसानों ने अपनी पारंपरिक खेती गेहूं और सोयाबीन की फसल को बोना छोड़ कर औषधीय पौधों की खेती करने की तरफ रुझान बढ़ा है। अगरकरा भी इन्हें में से एक है। जिसके दाम बहुत ज्यादा हैं और इसमें लागत बहुत कम आती है।

औषधि की मांग बढ़ने से उनके दामों में उछाल आया

सात माह की फसल: देखा जाए तो पांरपरिक फसलों में अब लागत बढ़ती जा रही है। वहीं भाव भी ठीक नहीं मिलते। जिसके चलते क्षेत्र के किसान ने अगरकरा नामक औषधीय पौधे अपनी करीब तीन एकड़ कृषि भूमि में लगाई है। धर्मेंद्र ने बताया कि वे गोविंद पाटीदार से अगरकरा का बीज नीमच मंडी से खरीदकर लाए थे। जिसका भाव एक हजार रुपए किलो था। धर्मेंद्र करीब 30 किलो बीज लाए थे। जो साढ़े तीन एकड़ में लगाए थे। बोवनी नवंबर में की थी। फसल की उम्र छह से सात माह होती है। सात माह में फसल पक कर तैयार हो जाती है। पौधे से जड़ों का उत्पादन आठ से दस क्विंटल प्रति एकड़ होता है।

30 हजार रुपए क्विंटल: मंडी में इस औषधीय पौधे की जड़ों की कीमत आम दिनों में 25 से 30 हजार रुपए प्रति क्विंटल होती है, लेकिन कोरोना में आयुर्वेदिक दवाओं की मांग बढ़ने से इसकी कीमत 35 से 40 हजार रुपए क्विंटल तक पहुंच गई है। वहीं पौधे में लगने वाले फूल भी दो से तीन हजार रुपए प्रति किलो बिकता है। जिससे किसान को अच्छा खासा मुनाफा मिलता है।

साढ़े छह लाख कुल आमदनी

किसान धर्मेंद्र बताते हैं कि वे 30 किलो बीज लाए थे। जिसे साढ़े तीन एकड़ में बोया। इस हिसाब से करीब साढ़े आठ हजार का बीज एक एकड़ में लगा। एक एकड़ में 10 हजार की खाद डाली थी। अब कटाई का खर्च 15 हजार एकड़ आएगा। कुल मिलाकर 35 हजार का खर्च एक एकड़ हुआ है। वहीं एक एकड़ में आठ से दस क्विंटल जड़ होगी। जिससे साढ़े तीन लाख की आमदनी होगी। चार क्विंटल भूसा होगा जो करीब आठ हजार का बिकेगा। तीन क्विंटल बीज का उत्पादन होगा। जिससे तीन लाख की आमदनी होगी। कुल आमदनी साढ़े छह लाख की होगी। एक एकड़ में 20 क्विंटल गेहूं होता है जिससे 40 हजार की आमदनी होती है।

जागत गांव हमारः लॉकडाउन में वापस गांव लौटे कठहा स्कूल के पुराने छात्रों ने जनसहयोग से 11 लाख एकत्र कर विद्यालय से लगी जमीन खरीदी और शाला विकास के लिए कर दी दान

कठहा स्कूल के पुराने छात्रों ने पेश की आत्मनिर्भरता की अनोखी मिसाल

दीपक गौतम, सतना

जन्मभूमि की माटी और मां के दूध का कर्ज अदा करते आपने कई बार देखा-सुना होगा। लेकिन शिक्षा के मंदिर का कर्ज उतारते नहीं। सतना जिले के अमरपाटन तहसील में कठहा स्कूल के पुराने छात्रों और ग्रामीणों ने जनभागीदारी और आत्मनिर्भरता की अनोखी मिसाल प्रस्तुत की है। जिसे हर कोई सुनकर वाह-वाह कर रहा हैं। आत्मनिर्भर भारत की यह तस्वीर सतना जिले के छोटे से गांव कठहा से निकल कर आई हैं। जहां कोविड-19 के संक्रमण काल के दौरान लॉकडाउन में वापस अपने गांव लौटे कठहा स्कूल के पुराने छात्रों ने अपने स्कूल के लिए जनसहयोग से 11 लाख रुपए की राशि एकत्र कर विद्यालय से लगी हुई जमीन खरीदी और स्कूल के निर्माण कार्यों के लिए दान कर दी।

अच्छे ओहदे पर पुराने विद्यार्थी: शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कठहा में पढ़ने वाले छात्र सांसद, विधायक, राष्ट्रीय कंपनियों एवं भाभा अनुसंधान जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों में अच्छे ओहदे पर रह चुके हैं। इसी स्कूल से पढ़ चुके हिंदुस्तान पेट्रोलियम के रीजनल मैनेजर कृपाशंकर गौतम, आईआईटी में प्रो. आरके साकेत, भाभा अनुसंधान के वैज्ञानिक रोहित द्विवेदी, कोषालय अधिकारी देवेंद्र द्विवेदी जब लॉकडाउन में अपने गांव लौटे तो उन्होंने सभी पुराने छात्रों और ग्रामीणों की सहायता से अपने स्कूल के लिए कुछ योगदान देकर शिक्षा मंदिर का ऋण चुकता करने की बात सोची।

जन सहयोग की अनोखी मिसाल

कठहा गांव से लगे आठ गांव के लोगों द्वारा अपने विद्यालय के लिए दिए गए योगदान और सामूहिक प्रयास की हर कोई सराहना कर रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग और प्रशासन को भी अब कठहा स्कूल में अतिरिक्त कक्ष बनाने और बच्चों के खेल मैदान विकसित करने का रास्ता साफ हो गया है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कठहा के पुरा छात्रों और ग्रामीणों ने आत्मनिर्भरता और जन सहयोग की अनोखी मिसाल प्रस्तुत करते हुए यह संदेश भी दिया कि हर सक्षम व्यक्ति को अपने शिक्षा का कर्ज अदा करना चाहिए। जिस स्थान से आपका भविष्य संवरा है, वहां से आगामी पीढ़ी का भी भविष्य निरंतर उज्जवल होता रहे।

स्कूल के लिए खरीदी एक एकड़ से ज्यादा जमीन

कोरोना काल में अपने गांव वापस लौटे पुराने छात्रों ने आपस में निर्णय कर स्कूल के बगल की एक एकड़ निजी भूमि क्रय करने का निर्णय लिया। ग्रामीणों और पुराने छात्रों के अंशदान के जन-सहयोग से साढ़े दस लाख की राशि एकत्र हो गई। कठहा स्कूल के विकास के लिए मातृभूमि गौरव सेवा संकल्प समिति नामक ट्रस्ट का गठन कर विधिवत पंजीयन कराया और स्कूल से लगी एक एकड़ 9 डिस्मिल कृषि योग्य जमीन निजी काश्तकार विवेक दहायत से साढ़े दस लाख रुपए में खरीदकर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अमरपाटन के माध्यम से कठहा विद्यालय के नाम सुपुर्द कर दी।

खल रही थी मैदान की कमी

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कठहा की स्थापना वर्ष 1932 में हुई थी। आसपास के लगभग 8 गांवों के बच्चे यहां पढ़ने आते हैं। छात्रों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अतिरिक्त कक्ष और खेल मैदान की सख्त जरूरत है। स्कूल की जगह संकीर्ण हो चुकी है और शासन द्वारा अतिरिक्त कक्ष और खेल मैदान के लिए स्वीकृति मिल सकती है। लेकिन इन निर्माण कार्यों के लिए विद्यालय के पास एक इंच भी जमीन नहीं थी।

मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में हो रही खेती

» कृषि वैज्ञानिकों का दावाः कैंसर, उच्च रक्तचाप, मधुमेह के लिए फायदेमंद

» वर्तमान में बाजार में काले गेहूं का भाव चार से छह हजार रु. प्रति क्विंटल

काला गेहूं कैंसर का 'काल'

संवाददाता, श्योपुर

मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में पिछले कुछ सालों में कैंसर के मरीज बढ़े हैं। ऐसे में किसानों ने कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर कैंसर में दवा की तरह काम करने वाले काले गेहूं की खेती शुरू की है। गुरुनावदा, आवदा और इंद्रपुरा गांव के किसानों ने पहली बार करीब 15 बीघा में काले गेहूं की बोवनी की है। फसल खेतों में लहलहा रही है। विशेषज्ञ बताते हैं कि काले गेहूं में एंथ्रोसाइनिन (प्लांट पिगमेंट) प्रचुर मात्रा में होता है।

यह एक प्राकृतिक एंटी आक्सीडेंट व एंटीबायोटिक है, जो कैंसर, हार्टअटैक, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, एनीमिया जैसे रोगों में काफी कारगर सिद्ध होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि काला गेहूं आम गेहूं के मुकाबले ज्यादा पैदावार देता है और दो से ढाई गुना महंगा बिकता है। वर्तमान में बाजार में इसका भाव चार से छह हजार रुपए प्रति क्विंटल है।

जले में बढ़े कैंसर मरीज

मिलावटी खाद्य सामग्री और तंबाकू के सेवन के कारण श्योपुर जिले में कैंसर के मरीजों की संख्या में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। कारण के मूल में जाने पर कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को इस रोग में दवा की तरह काम करने वाले काले गेहूं के उत्पादन की सलाह दी।

पंजाब से लाए बीज

गुरुनावदा गांव में कृषि स्नातक किसान भरतसिंह जाट ने तीन बीघा, आवदा में किसान जयदीपसिंह तोमर ने छह बीघा, इंद्रपुरा में दिनेश नागर ने तीन बीघा, सोईकला में सोनू गर्ग ने डेढ़ बीघा, प्रेमपुरा में किसान गुरुदीपसिंह ने डेढ़ बीघा और चोंडपुर में रामभरत बैरागी ने डेढ़ बीघा में पंजाब से बीज लाकर काले गेहूं की फसल बोई। यह अब खेतों में लहलहा रही है।

इनका कहना है

काले गेहूं का सेवन हर मौसम में किया जा सकता है, क्योंकि इसमें एंटी ऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होता हैं। इसके अलावा फाइबर, प्रोटीन, मैग्नीशियम जैसे जरूरी पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो कई बीमारियों से लड़ने में सक्षम हैं। इसमें आयरन अधिक मात्रा में होता है। इस वजह से कैंसर, रक्तचाप, मोटापा और मधुमेह के मरीजों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। इससे खून की कमी दूर होती है। साथ ही आंखों की रोशनी भी बढ़ती है।

डॉ. बीएल यादव, सीएमएचओ, श्योपुर

काला गेहूं सामान्य दिखने वाले गेहूं की ही तरह होता है। इसमें बालियां अधिक होती हैं। एक बीघा में 10 से 12 क्विंटल तक काला गेहूं पैदा हो सकता है। इसका बीज सामान्य गेहूं की तुलना में तीन गुना महंगा होता है। लेकिन अधिक फुटान होने से एक बीघा में महज 20 किलोग्राम बीज की ही जरूरत पड़ती है। जबकि सामान्य गेहूं में 40 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है।

डॉ. नीरज हाडा, विज्ञानी, बड़ौदा कृषि विज्ञान केंद्र

मार्च की आमद के साथ मंडी में सौंफ की सुगंध

» कृषि उपज मंडी को अब राजस्व की प्राप्ति होने लगी

» जनवरी से शुरू हुआ सीजन अब शबाब पर पहुंचा

बड़वानी। वित्तीय वर्ष में मंदी की मार झेल रही स्थानीय कृषि उपज मंडी को अब सौंफ की आवक से राजस्व की प्राप्ति होने लगी है। जनवरी से शुरू हुआ सौंफ का सीजन अब मार्च की आमद के साथ शबाब पर पहुंचने लगा है। सीजन में पहली बार रिकॉर्ड करीब सौंफ की आवक हो रही है। गौरतलब है कि मंडी अधिनियम में संशोधन के बाद मंडी में इस वित्तीय वर्ष में पिछले पांच वर्षों की तुलना में राजस्व की खासी कमी आई है। यहां तक कि बीते माहों में स्टाफ को वेतन की चिंता सताने लगी थी, वहीं जनवरी माह से शुरू हुआ सौंफ का सीजन शुरुआत से मंदा चल रहा था। फरवरी के पहले सप्ताह से सौंफ की आवक मंडी में बढ़ने से रौनक भी बढ़ने लगी है। सौंफ की खरीदी-बिक्री के लिए हजारों लोगों की भीड़ जुट रही है।

भावों में 40 प्रतिशत कमीः मंडी में सौंफ की बंपर आवक के बावजूद सौंफ के भावों में 30 से 40 प्रतिशत कमी आई है। इससे किसानों के चेहरे मुरझाए दिख रह हैं। गत दो सप्ताह में मंडी में सौंफ 50 रुपए से लेकर 190 रुपए प्रति किलो तक बिकी है।

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, गोपाल दास बंसल-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
हरदा, राजेन्द्र बिल्लोरे-9425643410
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
सागर, अनिल दुबे-9826021098
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
भिण्ड- नीरज शर्मा-9826266571
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272
सतना, दीपक गौतम-9923800013
रीवा-धनंजय तिवारी-9425080670
रतलाम, अमित निगम-70007141120
झाबुआ-नोमान खान-8770736925

कार्यालय का पताः- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादकः अजय कुमार द्विवेदी, संपर्क-9229497393, 9425048589, ईमेलः- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)